(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) No.

(b) As the project area is spread over two districts in two States, considerable time was taken to collect the required data from all the Units operating in this area. All the data has now been received and a decision is expected to be taken shortly.

### मध्य प्रदेश में रावि डाकघर

- 3145. श्री हुकम चन्द कछवाय: क्या संबार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) मध्य प्रदेश में कितने रावि डाकघर हैं तथा वे किन-किन जिलों में स्थित हैं; और
- (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कितने रात्रि डाकघर खोलने का सरकार का विचार है तथा किन किन जिलों में रात्रि डाकघर खोले जायेंगे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) 5; भोपाल, इन्दौर, ग्वालयर, जवलपुर तथा रायपुर जिलों में से प्रत्येक में एक-एक।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः इस समय कोई निश्चित सूचना देना संभव नहीं हैं।

## · दिल्ली में नकती राशन कार्ड

3146. श्री हुकम चन्द कछवाय: क्या खाख तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 1967 में लेकर आज तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये जिनके पास नकती राशन कार्ड थे और जिन्होंने उनका प्रयोग किया था;

- (ख) कितने व्यक्तियों को दण्ड दिये गये और कितने मामले अभी न्यायालयों, में निर्णयाधीन हें।
- (ग) उक्त अवधि में दिल्ली में ऐसे कितने राशन कार्ड पकड़े गये जिनका दुरु-पयोग किया जा रहा था और इन जब्त राशन कार्डों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और।
- (घ) चीनी, गेहूं तथा चावल के कोटे में सरकार को उनसे एक वर्ष में कितने यूनिटों की बचत हुई :

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे): (क) 93 व्यक्ति।

- (ख) 34 व्यक्तियों पर दोष सिद्ध हुआ और 59 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले निर्णयाधीन हैं।
- (ग) 16,450 राशन-कार्ड पकड़े गये थे जिसमें से 4,067 कार्ड रद्द कर दिए गए और शेष 12,383 कार्डों में जो अधिक नाम लिखें हए थे उन्हें कम कर दिया गया।
  - (घ) चीनी 46391 पृनिट गेहूं तथा चावल 84192 यूनिट

# मध्य प्रदेश के लिये चीनी का कोटा

- 3147. श्री हुकम चन्द कछवाय: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के खाद्य मन्द्री ने केन्द्र से राज्य के लिये चीनी के अधिक कोटे की मांग की हैं; और
- (ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

खाछ, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री क्राप्ता-साहिद शिन्दे): (क) राज्य सरकार के खाद्य विभाग से प्रतिमास 1,600 मीटरी टन अतिरिक्त आवंटन के लिये एक पव प्राप्त हुआ था।

(ख) राज्य सरकार को मुचित किया गया है कि आंश्रिक नियंत्रण की नीति के अन्तर्गत लगभग 12 लाख मीटरी टन चीनी नियंत्रित वितरण के लिये उपलब्ध होगी, और तदनसार राज्यों को प्रतिमास एक लाख मीटरी टन चीनी दी जा रही है। राज्य सरकारों के कोटे. नवम्बर, 1967 में आंशिक नियंत्रण की नीति के लाग होने के पहले जो कोटे दिये जा रहे थे उनके समान अनुपात से निर्धारित किए गए हैं और इन परिस्थितियों में लेवी चीनी से अतिरिक्त कोटे आंवटित करना सम्भव नहीं है ।

### ं मेरठ और दिल्ली टेलीफोन लाइन

3148. श्री हुकम चन्द कछवाय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि 11 फरवरी, 1968 को कुछ समाज-विरोधी लोगों न दिल्ली-मेरठ टेलीफोन लाइन काट दी थी और तारें चरा ती थीं जिसके फलस्वक्प मेरठ और दिल्ली के बीच संचार व्यवस्था बन्द हो गई थी:
- (ख) यदि हां, तो कितनी तारें चुराई गई थीं: और
- (ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति . गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संतद्-कार्य तथा संवार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० हु० गुजराल) : (क) जी, नहीं । '

(ख) तथा (ग), प्रश्न ही नहीं उठते ।

ALL INDIA SOIL AND LAND USE SURVEY

3149. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of FOOD AND AGRI-CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Adminis-

trative Reforms Commission has recommended for the merger of All India Soil and Land Use Survey Oraganisation with the Indian Council of Agricultural Research;

(b) if so, the decision taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). No such recommendation has been received so far from the Administrative Reforms Commission in this regard. The Government of India are, however, considering the transfer of such of the work of the AH India Soil and Land Use Survey Organisation as relates to research in soil classification, correlation, and preparation of soil map of the country, to the Indian Council of Agricultural Research. Part of this Organisation dealing with soil survey work in the catchments of river valley projects will remain under the Department of Agricul-

#### COOPERATIVE SUGAR MILL AT BARGARII (ORISSA)

3150. SHRI SRADHAKAR SUPA-KAR: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

- (a) the steps so far taken for setting up a Cooperative Sugar Mill at Bargarh in Orissa; and
- (b) the reasons as to why industrial licence to procure machinery, etc. has not been issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE. COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) An industrial licence was granted on 24-8-1966 for the establishment of a new 1250 tonne cooperative sugar factory at village Brahaguda, Tehsil Bargarh Distt. Sambalpur in Orissa.

(b) No separate licence is necessary for the purchase of plant and machinery.